प्रसार भारती
भारतीय प्रसारण निगम
आकाशवाणी केन्द्र शिमला
22.04.2026 / प्रादेशिक समाचार / 11:00बजे

शहरी निकाय चुनाव

राज्य निर्वाचन विभाग ने प्रदेश के 51 शहरी निकायों में चुनाव कार्यक्रम की घोषणा कर दी है और इन शहरी निकायों में आदर्श चुनाव आचार संहिता तत्काल प्रभाव से लागू हो गई है। राज्य चुनाव आयुक्त अनिल खाची ने बताया कि इनमें 4 नगर निगम सोलन, पालमपुर, मंडी व धर्मशाला और 25 नगर परिषद व 22 नगर पंचायतें शामिल हैं। उन्होंने कहा कि प्रदेश के इन शहरी निकायों में 17 मई को सुबह 7 बजे से दोपहर बाद 3 बजे तक मतदान होगा। नगर परिषद और नगर पंचायतों के मतों की गणना मतदान वाले दिन 17 मई को ही होगी जबकि चारों नगर निगमों के मतों की गणना 31 मई को होगा। अनिल खाची ने बताया कि इन निकायों में कुल 3 लाख 60 हज़ार 8 सौ 59 मतदाता अपने मताधिकार का प्रयोग करेंगे। इनमें एक लाख 80 हज़ार 9 सौ 63 पुरूष, जबकि एक लाख 79 हज़ार 8 सौ 82 महिला और 14 अन्य मतदाता हैं।

भाजपा प्रभारी नियुक्ति

आगामी नगर निगम व पंचायती राज चुनावों को लेकर भारतीय जनता पार्टी ने प्रदेश भर में नगर निगमों, जिला स्तर और प्रदेश स्तर पर चुनाव प्रभारियों व समितियों की विस्तृत घोषणा कर दी है। नगर निगम चुनावों के लिए घोषित प्रभारियों में धर्मशाला नगर निगम के लिए पवन काजल, सुधीर शर्मा और सचिन शर्मा, पालमपुर नगर निगम के लिए विपिन परमार, राजेश ठाकुर, त्रिलोक कपूर और रागिनी रकवाल जबकि मंडी नगर निगम के लिए पायल वैद्य, अनिल शर्मा, इंद्र सिंह गांधी और निहाल चंद शर्मा को जिम्मेदारी दी गई है। वहीं सोलन नगर निगम के लिए संजीव कटवाल, बलवीर वर्मा, रश्मिधर सूद, वंदना योगी, रतन सिंह पाल, डॉ. राजेश कश्यप और शैलेन्द्र गुप्ता को चुनाव संचालन का दायित्व सौंपा गया है। इसके साथ ही पंचायती राज व नगर निकाय चुनावों के लिए भी प्रदेश स्तर पर समिति गठित कर दी गई है, जिसमें प्रमुख प्रभारियों को जिम्मेवारी सौंपी गई है।

मुकेश अग्निहोत्री

उपमुख्यमंत्री मुकेश अग्निहोत्री आज ऊना जिला में हरोली के रोड़ा में स्थापित प्रदेश के पहले ऑटोमेटिड ड्राइविंग टेस्ट ट्रैक व ट्रैफिक पार्क का उद्घाटन करेंगे। इस परियोजना के शुरू होने के साथ ही प्रदेश को अपना पहला ऑटोमेटिड ड्राइविंग टेस्ट ट्रैक व ट्रैफिक पार्क मिलेगा। यह अत्याधुनिक ट्रैक ड्राइविंग लाइसेंस के लिए होने वाले परीक्षण को पूरी तरह तकनीक आधारित और पारदर्शी बनाएगा, जिससे मानव हस्तक्षेप कम होगा और पात्र अभ्यर्थियों का निष्पक्ष मूल्यांकन सुनिश्चित हो सकेगा। ट्रैफिक पार्क के माध्यम से आम जनता, विशेषकर युवाओं और बच्चों को यातायात नियमों के प्रति जागरूक किया जाएगा, जिससे सड़क सुरक्षा को बढ़ावा मिलेगा।

मिड–डे मील योजना

केंद्र सरकार द्वारा शुरू की गई मिड–डे मील योजना भारत सरकार का एक प्रमुख कार्यक्रम है। इस योजना का उद्देश्य सरकारी व सहायता प्राप्त स्कूलों के पहली कक्षा से लेकर आठवीं कक्षा तक के बच्चों को पौष्टिक भोजन प्रदान करना है। कुल्लू जिले के 7 शिक्षा खंडों के अंतर्गत 1 हज़ार 6 प्री–प्राइमरी, प्राइमरी तथा अपर प्राइमरी विद्यालयों में कुल 35 हज़ार 1 सौ 18 विद्यार्थियों को मिड–डे मील प्रदान किया जा रहा है विस्तृत ब्यौरे के साथ हमारे कुल्लू जिला संवाददाता...

केंद्र सरकार द्वारा शुरू की गई मिड–डे मील योजना, जिसे अब पीएम पोषण शक्ति योजना कर दिया गया है, भारत सरकार का एक प्रमुख कार्यक्रम है। इस योजना का उद्देश्य सरकारी व सहायता प्राप्त स्कूलों के पहली कक्षा से लेकर आठवीं कक्षा तक के बच्चों को पौष्टिक भोजन प्रदान करना है। व स्कूलों में बच्चों की उपस्थिति बढ़ाना और कुपोषण को कम करना है। कुल्लू जिले के 7 शिक्षा खंडों के अंतर्गत 1 हज़ार 6 प्री–प्राइमरी, प्राइमरी तथा अपर प्राइमरी विद्यालयों में कुल 35 हज़ार 1 सौ 18 विद्यार्थियों को मिड–डे मील प्रदान किया जा रहा है। इसके अलावा सभी 1 हज़ार 6 विद्यालयों में किचन गार्डन भी स्थापित किए गए हैं। इन सभी विद्यालयों में निर्धारित मेनू के अनुसार गुणवत्तापूर्ण एवं पौष्टिक भोजन उपलब्ध करवाया जा रहा है और इसके सार्थक परिणाम भी सामने आ रहे हैं। वित्त वर्ष

2025–26 के लिए जिला कुल्लू को इस योजना के अंतर्गत 7 करोड़ 49 लाख 64 हजार रुपये का बजट आबंटित किया गया। आकाशवाणी के लिए कुल्लू से आशीष शर्मा।

टीकाकरण अभियान

चंबा जिला में सर्वाइकल कैंसर से बचाव को लेकर स्वास्थ्य विभाग ने 14 वर्ष तक की बेटियों का टीकाकरण अभियान तेज कर दिया है। अब 14 वर्ष तक की बेटियों को सरकारी स्वास्थ्य केंद्रों पर एचपीवी वैक्सीन लगाई जा रही है। अभियान का उद्देश्य कम उम्र में ही बेटियों को इस गंभीर बीमारी से सुरक्षित करना है। जिला स्वास्थ्य अधिकारी डॉ कविता महाजन ने बताया कि स्वास्थ्य विभाग चम्बा को 4500 बेटियों को 3 मई तक ये वैक्सीन लगाने का लक्ष्य दिया गया है।

जनगणना

देश में जनगणना 2027 के पहले चरण के दौरान 26 लाख से अधिक परिवारों ने स्व–गणना सुविधा का लाभ उठाया है। रजिस्ट्रार जनरल के अनुसार, यह डिजिटल जनगणना में लोगों की बढ़ती भागीदारी का संकेत है। उन्होंने कहा कि ऑनलाइन जानकारी देकर लोग राष्ट्र निर्माण में अपना योगदान दे रहे हैं।यह सुविधा फिलहाल कई राज्यों में जारी है, जबकि कुछ राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में मकान सूचीकरण का काम भी शुरू हो गया है। जनगणना का दूसरा चरण, यानी जनसंख्या गणना, अगले वर्ष फरवरी में शुरू होगी।

....